कश्मीर समस्या के समाधान से ही भारत–पाक सम्बन्धों में सुधार संभव

DR. PREMLATA PARSOYA
ASSOCIATE PROFESSOR
UNIVERSITY OF KOTA, KOTA (RAJ.)

भारत–पाकिस्तान दक्षिण एशिया के दो प्रमुख और निकटतम पड़ौसी राष्ट्र है परन्तु इस भोगोलिक निकटता के विपरीत स्तर पर दोनों के राजनीतिक व रणनीतिक सम्बन्ध है। पाकिस्तान का जन्म ही एक तरह हठधर्मिता और जिद की वजह से हुआ था और तभी से उसका लक्ष्य भारत का विरोध और भारत को नुकसान पहुँचाना ही रहा है। जिस साम्प्रदायिकता के बीज के कारण भारत का विभाजन होकर पाकिस्तान निर्मित हुआ है वह बीज आज वटवृक्ष का रूप धारण कर चुका है। विभाजन के ऋण के बंटवारे, नहरी पानी का बंटवारा, शरणार्थियों की समस्या क्षेत्र का बंटवारा ..... सभी का समाधान लगभग कर लिया गया था, हां, कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में नेहरू जी द्वारा पहुँचाने के कारण, वह अनसुलझी रह गई और भारत–पाक के द्विपक्षीय सम्बन्धों के लिए वह नासूर साबित हो रही है। भारत–पाकिस्तान के विभाजन के बाद जिस तरीके से एक–दूसरे देश में भागना पड़ा, वही दर्दनाक मंजर दोनों के दिलों में भावनात्मक दूरियां पैदा करने वाला था। हालांकि विभाजन से पूर्व यह अनुमान किसी ने भी नहीं लगाया था कि दोनों मुल्क न केवल भोगोलिक रूप से विभाजित हो रहे है अपितु हर तरह से दूरियों ने अपनी जड़े जमा ली है।

जैसा कि डॉ. जे.एन. दीक्षित ने कहा है कि 1946 में पाकिस्तानी और भारतीय नेताओं का मानना था कि विभाजन एक साफ सुथरा अलगाव होगा, जो एक शान्तिपूर्ण और स्थायी सम्बन्ध का आधार निश्चित करेगा परन्तु यह धारणा शुरू से ही गलत सिद्ध हुई। पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त और सिन्ध में बड़ी संख्या में रह रहे हिन्दुओं, जिन्हें पाकिस्तान में क्षेत्रों के शामिल होने के बाद वहाँ से भागना पड़ा, कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें विभाजन की पीड़ादायिनी प्रक्रिया को झेलना पड़ेगा।[1] यद्यपि भारत ने प्रारम्भ से ही पाकिस्तान के प्रति उदारतापूर्वक रवैया अपनाया परन्तु प्रत्युत्तर में उसे निराशा ही हाथ लगी। 1948, 1965, 1971, 1999 में चार बार भारत के साथ युद्ध छेड़ चुका है और हर बार उसे मात खानी पड़ी परन्तु वह उपनी नापाक करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। हर समय वह आतंकवादी गतिविधियों को भारत के क्षेत्र में अंजाम देता रहता है और भारत के प्रति अनजानी आशंका से ग्रसित रहता है जबकि भारत अपने दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के प्रति बिग ब्रदर की भूमिका निभाता आया है परन्तु पाकिस्तान भारत की गुड विल को कभी आंक ही नहीं सका इसलिए कितनी ही बार दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ताऐ आयोजित हुई परन्तु वो बेनतीजा ही समाप्त हो गई।

भारत–पाकिस्तान के 20वीं शताब्दी के द्विपक्षीय सम्बन्धों पर यदि दृष्टिपात किया जाये तो निराशा ही हाथ आती है। यद्यपि भारत की तुलना में पाकिस्तान, किसी भी दृष्टिकोण से अधिक सक्षम नहीं है परन्तु अन्य ताकतों का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष समर्थन जैसे पूर्व में चीन, अमेरिका और वर्तमान में चीन से मिल रहा हैं क्योंकि शीत–युद्ध के दौर में भारत–यू.एस. सम्बन्ध अधिक अच्छे नही थे क्योंकि भारत–सोवियत संघ मैत्री अमेरिका को नागवार गुजरी और चीन भी भारत का प्रमुख प्रतिद्वन्दी राष्ट्र था जिसके इरादे 1962 में जग–जाहिर हो चुके थे। इसलिए चीन और अमेरिका ने भारत–सोवियत संघ मैत्री के समानान्तर या उसकी ताकत को खत्म करने हेतु पाकिस्तान को सैन्य समर्थन देना शुरू किया। पाकिस्तान सीटो(SEATO) और सेन्टो (CENTO) का सदस्य भी बना। इसी तरह चीन ने भी भारत की शक्ति को सन्तुलित करने हेतु पाकिस्तान को परमाणु तकनीक व सामर्थ्य प्रदान कर उसे आणविक शक्ति बना दिया।

1965 व 1971 के युद्धों में पाकिस्तान को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी परन्तु भारत को उकसाने वाली कार्यवाहियां करने से पाकिस्तान बाज नहीं आया। भारत ने एकतरफा सदाशयता का परिचय दिया जिसे भी शायद पाकिस्तान ने हमारी कमजोरी ही समझा। 1948 में भारतीय सैनिकों द्वारा कश्मीर को उग्रवादियों (कबाइलियों) को पूर्ण रूप से खत्म करने में सफलता मिलने ही वाली थी परन्तु जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट् संघ में भेज दिया। इसी तरह 1965 व

1971 के युद्ध में भारतीय सैनिकों के बलिदान द्वारा जीते गये भू–क्षेत्रों को भारत ने ताशकन्द और शिमला समझौते की टेबल पर बैठकर पुनरू लौटा दिया। चूँकि भारत विश्व शान्ति और शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व में विश्वास रखने वाला देश है इसलिए अपनी ओर से पाकिस्तान से वार्ता व शान्ति प्रक्रिया की नीति में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी।

1983 में भारत की तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने विदेशमन्त्री नरसिम्हाराव को पाकिस्तान की यात्रा पर भेजा। इस यात्रा के दौरान हथियारों की आपूर्ति पर भारत ने दबाव डाला लेकिन पाकिस्तान भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए बीच–बीच में सीमाओं पर निरन्तर युद्ध जैसी स्थिति बनाये रखा और भारत के आन्तरिक मामलों में दखल देता रहा।[2] भारत द्वारा 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण करने पर पाकिस्तान की तरफ से ये वक्तव्य जारी हुए कि 'घास खायेंगें पर बम बनायेंगें'। इनसे प्रतीत होता है कि वह केवल भारत व उसकी शक्ति के समानान्तर ही अपना आकलन करता है। इन्दिरा गॉधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी के समय भी यद्यपि तनाव व्याप्त रहा परन्तु आपसी बातचीत की प्रक्रिया से सम्बन्ध सुधारों की आशा भी बलवती होती गई। इसी समय एक–दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं करने का संकल्प दोहराया गया तथा व्यापारिक सम्बन्धों की तरफ भी ध्यान देना शुरू किया तथा व्यापारिक समझौता भी किया गया तथा लगभग 40–42 वस्तुओं को आयात सूची में रखा गया। परन्तु इसी दौर में भारत में खालिस्तान की मांग को लेकर जो आन्दोलन चल रहा था उसके पीछे आई एस आई का प्रमुख हाथ था तथा वहीं से भारतीय उग्रवादियों को अस्त्र–शस्त्र व धन मुहैया करवाया जा रहा था।

1980 के दशक में विश्व स्तर पर क्षेत्रीय एकीकरण के प्रयत्नों की कड़ी में दक्षिण एशिया में सार्क(SAARC) की स्थापना पर विचार–विमर्श चल रहा था, जिसमें भारत–पाकिस्तान दानों ही प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। नव शीत–युद्ध के दौर में जब सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजी तो अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को और अधिक आर्थिक व सैन्य सहायता उपलब्ध करवाई गई और उक्त सामग्री का सीधा प्रयोग भारत पर किया जा सकता है इसकी आशंका भारत ने अमेरिका के सामने जाहिर कर दी गई थी परन्तु सामग्री आपूर्ति बनी रही। पाकिस्तान के कारण शीत युद्ध की दक्षिण एशिया तक दस्तक हो गई।

शीत युद्धोपरान्त भारत–पाक

यघपि अब तक का इतिहास सर्वाधिक विवादास्पद ही रहा था परन्तु भारत द्वारा भरपूर कोशिश यही रही कि वार्ता द्वारा आपसी विवादों का हल निकाला जाये। इसी पहल के परिणामस्वरूप 1991–92 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार, अप्रेल 1991 में दोनों देशों ने दो समझौतों पर हस्ताक्षर किये, जिसमें सैनिक अभ्यासों की सूचना पूर्व में दी जाने की बात शामिल थी और एक–दूसरे देश की वायु सीमा का उल्लघंन न करने की बात भी थी। भारत–पाक के शासनाध्यक्ष आपस में विभिन्न मंचों पर मिलते रहे, वार्ता होती रही परन्तु आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियां भी पाकिस्तान की तरफ से जारी रही इसीलिए दोनों के सम्बन्धों में स्थायी सुधार नहीं आ सका। जैसा कि सुरेन्द्र कुमार मिश्र ने कहा है कि पाकिस्तान उपनी खुफिया एजेन्सी ISI के माध्यम से इस क्षेत्र में अपनी विस्फोटक कार्यवाही करने के लिए बांग्लादेश, नेपाल और भारत में सक्रिय दो दर्जन से अधिक इस्लामी आतंकवादी गुटों को तैयार कर चुका है। इन इस्लामी आतंकवादी गुटों को 'लश्कर–ए–तोयबा' और 'तालिबान मिलिशिया' की भॉति संगठित एवं प्रशिक्षित किया जा रहा है।[3] 18–21 अक्टूबर, 1993 के बीच साइप्रस में राष्ट्र मण्डल खेलों के दौरान भारत के विदेश सचिव जे.एन. दीक्षित और पाकिस्तान के विदेश सचिव शहरयार खान के बीच तीन बैठकें हुई। ये वार्ताऐं जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र में हजरतबल दरगाह में आतंकवादियों की घुसपैठ की पृष्ठभूमि में हुई।[4] हालांकि पाकिस्तान सरकार भी तनाव पूर्ण सम्बन्धों से खुश नहीं हैं, अर्थव्यवस्था का काफी हिस्सा उसे सुरक्षा व अस्त्र–शस्त्रों पर खर्च करना होता है जिससे उसके विकासात्मक कार्य भी नहीं हो पाते हैं। पाकिस्तान की जनता भी अमन चैन और भारत के साथ शान्ति वाले सम्बन्धों की चाहत ही रखती है परन्तु वहॉ सेना तथा आई एस आई सरकार से भी अधिक शक्तिशाली है तथा निर्णय लेने की स्थिति में है। वहॉ की सरकार भी तनावपूर्ण माहौल से परेशान है और इसे खत्म करने की अपेक्षा भी रखती है। इसी अपेक्षा को जे.एन. दीक्षित ने अपनी पुस्तक में प्रदर्शित किया है, 2 जनवरी 1994 को उनकी (दीक्षित) पाकिस्तान की प्रधानमन्त्री बेनजीर भुटटो से मुलाकात हुई। बेनजीर ने अत्यन्त भावनात्मक और विवेकशील टिप्पणी की, कि भारतीयों और पाकिस्तानियों की दो पीढ़ियां कश्मीर मुद्दे से

प्रभावित रही है। इस दुःखद परिस्थिति को जारी नहीं रहने देना चाहिए। हमें इस समस्या को सुलझाना चाहिए और लाभदायक सहयोग व सम्बन्धों में सामान्यता के लिए प्रयास करना चाहिए।[5] परन्तु पाकिस्तान सरकार के ऊपर भी सर्वोच्च सत्ता है जो वास्तव में वहां की सम्प्रभु हैं। इसी आई.एस.आई. ने 1993 में भारत की वाणिज्यिक नगरी मुम्बई में बम विस्फोट किए ताकि भारत की अन्तराष्ट्रीय स्तर पर साख खराब हो सके।

1997 में भारत के प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल द्वारा 'गुजराल सिद्धान्त' की धोषणा की गई जिसमें बिना किसी अपेक्षा के इकतरफा सहायता पड़ौसी देशों को देने की बात निहित थी ताकि दक्षिण एशिया के राष्ट्रों का समग्र विकास हो सके। गुजराल सिद्धान्त में पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों की भी विस्तृत व्याख्या की गई थी। पाकिस्तानी शासक नवाज शरीफ व भारतीय शासक गुजराल में व्यक्तिगत मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे परन्तु वो कश्मीर मुद्दे पर कभी बात नहीं कर पाये क्योंकि उन्हें यह भय था कि दोनों देशों के बीच मुश्किल से सकारात्मक हुआ वातावरण कहीं, पुनः नकारात्मक नहीं बन जाए।

11 मई, 1998 में भारत ने पाँच परमाणु परीक्षण करके परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा हो गया और 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एक साथ छः परमाणु परीक्षण करके भारत के समकक्ष आ गया। इससे दक्षिण एशिया में हथियारों की दौड़ को अप्रत्यक्ष बढ़ावा मिला। यद्यपि भारत ने राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा हेतु परमाणु परीक्षण किये थे क्यों कि विश्वस्त सूत्रों से खबर थी कि पाकिस्तान आन्तरिक रूप से परमाणु बम क्षमता चीन तथा अमेरिका से प्राप्त कर चुका था और भारत पर कभी भी हमला कर सकता था। अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सी सी.आई.ए. के हवाले से अमेरिकी टेलीविजन ने भी अपने एक प्रसारण में बताया कि पाकिस्तान ने सात परमाणु बम बना लिए है एवं प्रत्येक बम द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर गिराये गए अणुबम से भी अधिक विनाशकारी है। इस प्रसारण में यह भी बतलाया गया कि वर्ष 1990 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच काफी तनाव बना हुआ था, तब पाकिस्तान ने कम से कम दो बमों का भारत पर प्रयोग करने का मानस बना लिया था।[6]

पाकिस्तान के साथ जब भी वार्ता प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है तब प्रत्युत्तर में कोई धमाका या विमान अपहरण जैसा उपहार ही भारत को मिला है। 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद के माहौल को ठीक करने के लिए भारत ने बस कूटनीति द्वारा दानों देशों की जनता के दिलों को जोड़ने का काम किया। दिल्ली–लाहौर सीधी बस सेवा प्रारम्भ की गई और खास बात ये थी कि भारत के प्रधान मन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं बस द्वारा दिल्ली से लाहौर गये। जम्मू–कश्मीर सहित सभी मुद्दों के समाधान हेतु ''लाहौर घोषणापत्र'' भी जारी किया परन्तु पाकिस्तानी सेना व आई एस आई को यह मन्जूर नहीं होता कि भारत–पाक सम्बन्ध सुधरे, इसलिए बस कूटनीति का जवाब पाकिस्तान द्वारा 'कारगिल प्रकरण' द्वारा दिया गया।

यघपि भारतीय सैनिकों की काबिलियत और साहस के आगे पुनरू पाकिस्तान को मात खनी पड़ी परन्तु वह बुरे मन्सूबे छोड़ नहीं पाता। दिसम्बर, 1999 में काठमाण्डू से भारतीय वायु सेना के एक विमान 1–C–814 का अपहरण करवा लिया और सभी यात्रियों को सुरक्षित छुड़ाने के बदले भारत को तीन कुख्यात आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। 21वीं सदी की शुरूआत भी वार्ता प्रक्रिया द्वारा की गई। जुलाई, 2001 में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच आगरा में वार्ता हुई परन्तु परिणाम वही 'ढाक के तीन पात' रहा और दिसम्बर 2001 में भारतीय संसद पर आतंकवादी हमले द्वारा पाकिस्तानी मन्सूबे उजागर हुए। यही एक प्रक्रिया सी बन गई थी कि जब भी दोनों के बीच शान्ति प्रक्रिया की कोई पहल की जाती तो पाकिस्तान द्वारा कोई न कोई आतंकी हमला करवा दिया जाता। कश्मीर दोनों के सम्बन्ध सामान्य नहीं हो सकते। गृहमन्त्रालय की 2005 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अकेले जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

7

	2001	2002	2003	2004
Incidents	4522	4038	3401	2526
Civil Killed	996	1008	795	707
Terrorist Killed	2020	1707	1495	976
Foreign Terriorist Killed	625	508	470	289
SFS Killed	536	453	795	281

पाकिस्तान द्वारा कई हजारों कश्मीरियों को आतंकवादी गतिविधियों में प्रशिक्षित किया गया है उन्हें हथियार उपलब्ध करवाये जाते है।जम्मू और कश्मीर में कार्यरत् सक्रिय आतंकवादी समूह जमात–ए–इस्लामी को आई.एस.आई. द्वारा धन दिया जाता है।

नवम्बर, 2008 की घटना, मुम्बई में ताज होटल पर आतंकवादी हमला, के बाद दोनों की स्थिति और गम्भीर हो गई। यह विचार दिमाग में कौंधता है कि आखिर पाकिस्तान क्यों भारत के साथ सम्बन्ध सामान्य नहीं करना चाहता जबकि किसी भी क्षेत्र में भारत से बढ़कर नहीं है। जे.एन.यू. के अन्तराष्ट्रीय राजनीति के प्रो. अमिताभ मट्टू के अनुसार कश्मीर असली घटना स्थल है, पाकिस्तान के लिए यह अब भी केन्द्रीय मुद्दा है, हम मानें या न मानें, यह उसके लिए बहुत भावनात्मक मुद्दा है, इस मुद्दे को छेड़ते ही पाकिस्तान में सबसे खतरनाक विचारधाराएँ उभर कर आती है।[8] भारत दक्षिण एशिया में सदैव दाता की भूमिका में रहा है और पड़ौसी राष्ट्रों के आर्थिक सामाजिक विकास में सहायता देता रहा हैं। पाकिस्तान अच्छे सम्बन्ध रखकर भारत से काफी लाभ प्राप्त कर सकता है परन्तु वह तो सदैव भारतीय शक्ति के प्रति आशंकित रहा हैं। पाकिस्तान किसी भी फील्ड में न भारत से आगे है न ही रहेगा, ये एस.पी. दिवाकर ने अपने लेख में बताया है – कि पाकिस्तान सभी पैमानों पर भारत से पीछे ही रहेगा–**आगे रहेगा भारत**

9

वर्ष		भारत	पाकिस्तान
2010	आबादी (अरब में)	1.178	0.169
	प्रति व्यक्ति जीडीपी	1055	975
2020	आबादी (अरब में)	1.369	0.206
	प्रति व्यक्ति जीडीपी	1769	1183
2030	आबादी (अरब में)	1.555	0.246
	जीडीपी	2683	1773

(GDP डॉलर में), (आबादी अरब में)

पाकिस्तान, भारत के प्रति नकारात्मक रवैया छोडकर यदि आर्थिक–व्यापारिक, सांस्कृतिक सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाये तो दक्षिण एशिया की विश्व स्तर पर स्थति बहुत अच्छी होगी।

भारत–पाकिस्तान के बीच सबसे विवादास्पद मुद्दा जम्मू–कश्मीर को लेकर ही है और इस मुद्दे का वह अन्तराष्ट्रीयकारण का प्रयास भी करता रहता है। वह बार–बार इस क्षेत्र में संघर्ष विराम तोड़ता रहता हैं। जम्मू–कश्मीर के क्षेत्र पर आज तीन देशों का अधिकार है इसे निम्न चित्र द्वारा समझा जा सकता है –

वर्ष	–	**देश**	–	**क्षेत्र**
1947	–	भारत	–	222, 236 वर्ग कि.मी. (लगभग)
संघर्ष और हमले द्वारा पाक के पास गया	–	पाकिस्तान	–	78, 114 वर्ग कि.मी. (लगभग)(च्ज्ञ)
	–	चीन	–	42, 685 वर्ग कि.मी. (अक्साईर्चिन) 5, 180 वर्ग कि.मी. (पाकिस्तान ने 1965 में चीन को दे दिया)
वर्तमान में	–	भारत	–	101, 437 वर्ग कि.मी. (लगभग)

इस तरह तीन देशों के अधीन जम्मू–कश्मीर की स्थिति विकास की दृष्टि से भी अच्छी नहीं हैं और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद ने वहां की स्थिति को अत्यन्त दयनीय बना दिया है। आजादी के बाद से ही जम्मू–कश्मीर को कभी युद्ध के संकट का दौर झेलना पड़ा तो कभी आतंकवाद की त्रासदी का सामना करना पड़ा। विकास की गति पकड़ना तो दूर, यहां के वाशिन्दे सामान्य सुविधाओं के लिए भी तरसते है।[10]

आंकड़ों पर दृष्टि डाली जाए तो 14 जनवरी 2013 के राज. पत्रिका के अनुसार 1988 में जम्मू–कश्मीर में मरने वालों की संख्या 31 लगभग थी वही 2001 में लगभग 3,552 हो गई थी। हालांकि यह संख्या 2011 में मात्र 164 हो गई थी परन्तु आज भी कश्मीर में कभी भी आतंक अपनी भयावह प्रकृति प्रदर्शित करता रहता है। 2017 के पिछले वर्ष में कश्मीर में आतंकवादी हत्याओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है जो कि मानवीयता पर करारी चोट है।

पाकिस्तान के साथ बातचीत की प्रक्रिया को अटल बिहारी वाजपेयी ने बस कूटनीति द्वारा शुरू किया जिसे मनमोहन सिंह ने भी निरन्तर बनाये रखा। नरेन्द्र मोदी ने भी अपने शपथ ग्रहण समारोह में दक्षिण एशिया के सभी शासकों को बुलाकर पड़ौसी राष्ट्रों के प्रति मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की शुरूआत की परन्तु पाकिस्तान का इस भावना का सकारात्मक प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। हाँ, ये भी सत्य है कि मोदी जी अच्छे सम्बन्धों की पहल में अग्रणी है परन्तु इस पहल के पीछे इकतरफा राष्ट्र हितों की कुर्बानी करने वाले भी नहीं है। आज जम्मू–कश्मीर के युवा भी दिग्भ्रमित होकर भारत के विरूद्ध नारेबाजी करके, स्थायी सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाकर और भारतीय सैनिकों पर पत्थरबाजी करके पाकिस्तानी नापाक मंसूबों को हौंसला दे रहे है क्योंकि आई एस आई कश्मीरी जनता तक अपनी पकड़ बनाती जा रही है। 1947 से 2017 तक हजारों लोग। सैनिक पाकिस्तानी आतंक की भेंट चढ़ चुके है अब इस पर विराम लगाने का समय आ गया है। यद्यपि भारत–पाकिस्तान के बीच 1972 में सम्पन्न शिमला–समझौते में यह प्रावधान या कि बिना किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के ये दोनों राष्ट्र अपने ही स्तर पर अपने विवादों का शान्तिपूर्ण समाधान खोजेंगे परन्तु अब पाकिस्तान की नापाक हरकतों को रोकना अति आवश्यक हो गया है।

मामला भारत–पाक का है लेकिन जब भड़काने में तीसरा होता है तब सुलझाने में भी तीसरे–चौथे की मदद बुरी नहीं है। हमने बहुत सहन कर लिया। अब सहनशक्ति की ज्यादा परीक्षा ठीक नहीं। केन्द्र सरकार को अपनी सारी कूटनीतिक दक्षता पाकिस्तान को हद में रहने के लिए लगानी चाहिए। अन्यथा युद्ध तो आखिरी रास्ता है ही। जनवरी, 2013 में भी पाकिस्तान ने एक कायराना हरकत करते हुए मथुरा के वीर हेमराज को न केवल मारा, बल्कि उसका सर काटकर ले गये।[11]

सेना द्वारा जारी अंकड़ों को देखकर पता चलता है कि कितने भारतीय सैनिकों ने जान गंवाई हैं। ये इस ग्राफ से पता चलता है दृ

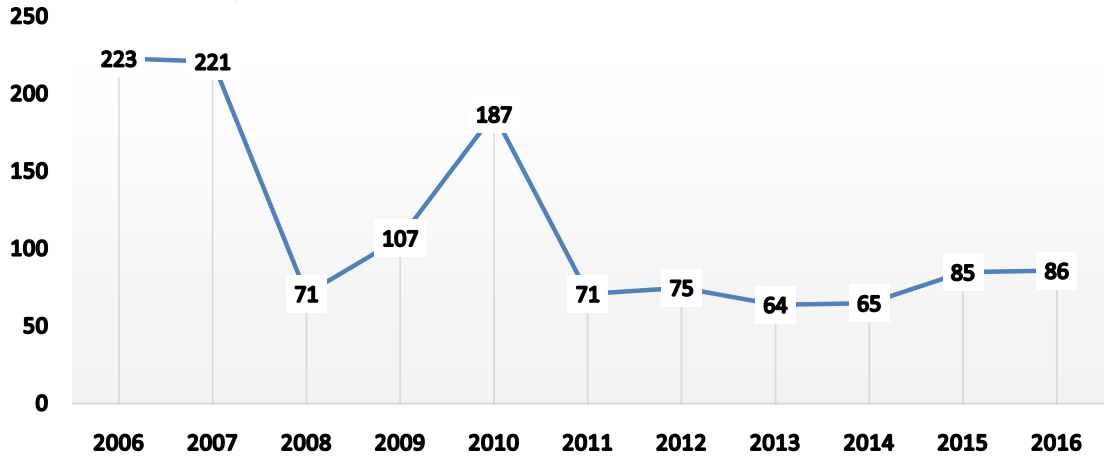

(स्त्रोत– राजस्थान पत्रिका, 21 जनवरी, 2018)

इन आंकडो से पता चलता है 1084 जवानों ने पाकिस्तानी फायरिंग, आतंक निरोधी ऑपरेशन्स ..... आदि में अपनी जान गंवाई हैं। इन जवानो के परिवारों के जख्मों व पीड़ाओं के बारे में सोचकर ही रूह कांपती है क्योंकि एक जवान के पीछे उसको पूरा परिवार ही पीड़ित हो जाता है। अब ज्यादा सहने की भी जरूरत नहीं हैं। हमारे प्रधानमन्त्री मोदी जी के नेतृत्व संभालने के समय यह आशा बलवती हो गई थी अब कश्मीर सहित सभी समस्याओं का समाधान हो सकेगा तथा पाकिस्तान को भी उसी की भाषा व हरकत के अनुसार प्रत्युत्तर दिया जायेगा। जब पहले पठानकोट और सितम्बर, 2016 में पाकिस्तान स्थित जैश–ए–मोहम्मद द्वारा भारत के उरी सैनिक ठिकाने पर हमला किया तो यह आवश्यक हो गया था कि माकूल जवाब दिया जाना चाहिए। लगभग 10–11 दिन बाद भारतीय सेना द्वारा पी ओ के में नियन्त्रण रेखा को पाक करके सर्जिकल स्ट्राइक की कार्यवाही को अन्जाम दिया जोकि हमारी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव था और बहुत समय से समय की मांग भी था। क्योंकि पाकिस्तान सदैव भारत की गुडविल का जवाब नकारात्मक रूप से ही दे रहा था जिसे इस चित्र द्वारा समझा जा सकता हैं –

भारत की सोच व कार्य	पाकिस्तान का जवाब
मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना की भावना	भारत को नुकसान पहुॅचाना
वार्ता प्रक्रिया की पहल	आतंकी धमाका
समझौते व सम्बन्ध सुधार की प्रक्रिया अपनाना	संघर्ष विराम का उल्लंधन
बस कूटनीति अपनाना	कारगिल पर कब्जा करना
आगरा शिखर वार्ता	भारतीय संसद पर हमला
शपथ ग्रहण में बुलाना व जन्म दिन की बधाई देना	पठानकोट, उरी सैनिक ठिकानों पर हमला

इन परिस्थितियों के मद्देनजर अब स्पष्ट होता है कि कश्मीर सहित पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दों का यथाशीघ्र करना चाहिए। पाकिस्तान की मंशा सदैव यह रहती है कि उसके साथ किसी अन्य मुद्दे पर बातचीत की जाए तो वह कश्मीर मुद्दे को बीच में लाकर वार्ता को बेनतीजा खत्म कर देता है और इस मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का भी दबाव डालता हैं। अब भारत को भी अपनी विदेश नीति, खासकर पाकिस्तान के प्रति खास तरीके से क्रियान्वित करनी होगी। वैसे अब तक भारत ने इकतरफा शान्ति व मित्रता की नीति अपनाई है और पाकिस्तान की हर नकारात्मक गतिविधि को नजरअन्दाज कर दिया और फिर से वार्ता प्रक्रिया की पहल भी शुरू कर दी इससे हमारे पड़ौसी मुल्क ने अपनी आदतों में सुधार का कोई प्रयास नहीं किया। पाकिस्तान की भूमि से आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया जाता है उन्हें अस्त्र–शस्त्र और धन प्रदान किया जाता है, इस बात को अप्रत्यक्ष रूप से सभी जानते थे परन्तु सामने इसे स्वीकार करते हुए पाकिस्तान पर इसे खत्म करने का दबाव नहीं बनाते और पाकिस्तान को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के समान स्थान मिलता रहता हैं।

अब विश्व स्तर पर पाकिस्तानी हरकतों का पर्दा उठता जा रहा है और पाकिस्तान पर वरदहस्त बनाने वाले अमेरिका ने भी उसकी करतूतें पहचानकर उसे आर्थिक सहायता देने से मना किया हैं। पंजाब विश्वविद्यालय के प्रो. दीपक के. सिंह के अनुसार अमेरिका ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। डोनाल्ड ट्रम्प ने साल (2018) के पहले ट्वीट में कहा कि अमेरिका ने 15 वर्षों के दौरान मूर्खतापूर्ण तरीके से पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर की सहायता की है लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान से झूठ और छल ही मिला है। इसके अलावा अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को दी जाने वाली 25.5 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता पर भी रोक लगा दी है।[12] यही अमेरिका था, जिसने पाकिस्तान को सदा भारत के समकक्ष रखकर व्यवहार किया था परन्तु आज उसकी हकीकत जानकर अमेरिका ने अपनी नीति को परिवर्तित कर लिया इसे ही समय के साथ चलना कहते है।

हालांकि अभी चीन, भारत का ध्यान पाकिस्तान पर केन्द्रित रहे इसलिए पाकिस्तान को वह हर तरह का समर्थन और सहायता दे रहा हैं सी.पी.ई.सी. उसकी इसी नीति का परिणाम है तथा भारत तक सामरिक परिस्थितियों की पहुंच बनाने के लिए दक्षिण एशिया के सभी राष्ट्रों में आर्थिक विकास करवाता जा रहा हैं और पाकिस्तान में भी वह इसी नीति पर चल रहा है। चीन और पाकिस्तान की मित्रता कौटिल्य के मण्डल सिद्धान्त के आधार 'शत्रु का शत्रु–मित्र' पर टिकी है इसलिए चीन, भारत को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान को परमाणु क्षमता सम्पन्न भी बना चुका है तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उसका समर्थन करता नजर आता है।

अन्ततः यही कहा जा सकता है कि कश्मीर में होने वाली सैनिकों की कुर्बानियों पर विराम लगाया जाए। पाकिस्तान से एक बार फाइनली दो–टूक शब्दों में कहना चाहिए कि जब तक वह आतंकवादी गतिविधियों के प्रसारण व प्रशिक्षण को खत्म नहीं करेगा तब तक उसके साथ किसी भी प्रकार के कूटनीतिक, राजनीतिक सम्बन्ध बनाये नहीं रखे जा सकते और कश्मीर विवाद के हल किए बिना और किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं की जा सकती। आज पाकिस्तानी आतंकवादी, कश्मीर में काफी गहरी जड़े जमा चुके है, वहॉ के लोगों का जीवन दूभर होता जा रहा हैं। वहां के नागरिक हर वक्त खौफ में जीते है। घर से बाहर निकलते समय वहां के बच्चे, नागरिक, महिलाएं सभी के मन में यह भय व्याप्त रहता है कि शाम को सही सलामत घर पहुचेंगे या नहीं ..... ?

इसके अतिरिक्त चाहे द्विपक्षीय वार्ता या पाकिस्तान जिद करे तो तीसरे और चौथे पक्ष की मध्यस्थता भी ली जा सकती है। एक पक्ष पाकिस्तान की मांग वाला हो सकता है तो दूसरा पक्ष भारत की इच्छानुसार हो सकता है परन्तु भारत–पाकिस्तान सम्बन्धों के लिए नासूर बन चुकी कश्मीर समस्या को यथासंभव समाधान किया जाना चाहिए। पाकिस्तान में सरकार के समानान्तर भले ही सेना की स्थिति हो या आई. एस.आई. की परन्तु वहां की जनता भी अमन–चौन चाहती है। जनता के हितों का कुठाराघात किसी भी राष्ट्र में उचित नहीं कहा जा सकता। इस समस्या के तीन राष्ट्र भारत, पाकिस्तान, चीन अभिन्न हिस्से है और ये बातचीत द्वारा सुलभ समाधान ढूंढ सकते है। ये तीनों के लिए ही अच्छा होगा और खासकर पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि वह अस्त्र–शस्त्रों पर किये जाने वाले खर्च को आर्थिक–सामाजिक विकास कार्यों में लगा सकेगा।

सन्दर्भ :–

1. जे.एन. दीक्षित – भारत–पाक सम्बन्ध, (युद्ध और शान्ति में) पृष्ठ दृ 117
2. डॉ. मुनेष कुमार – भारत–पाक सम्बन्ध–एक तुलनात्मक विश्लेषण डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि., नई दिल्ली, पृष्ठ दृ 141–142
3. सुरेन्द्र कुमार मिश्र – बांग्लादेशी धुसपैठ व भारतीय सुरक्षा राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृष्ठ – 172
4. जे. एन. दीक्षित – पूर्व उद्धृत, पृष्ठ – 328
5. जे. एन. दीक्षित – पूर्व उद्धृत, पृष्ठ – 330
6. शीला ओंझा – समकालीन भारतीय विदेश नीति, भाग – 3 श्यामप्रकाशन, जयपुर, पृष्ठ – 63
7. वर्लड फोकस, जुलाई 2006, पृष्ठ – 05
8. इण्डिया टुडे, 11 नवम्बर, 2009, पृष्ठ – 42
9. इण्डिया टुडे, 22 अगस्त, 2012, पृष्ठ – 45
10. राजस्थान पत्रिका, 26.11.2014 सम्पादकीय पृष्ठ
11. राजस्थान पत्रिका, 22 जनवरी 2018, संपादकीय पृष्ठ
12. राजस्थान पत्रिका, 3 जनवरी 2018, संपादकीय पृष्ठ